उत्तराखंड की ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पलायन के सामाजिक एवं आर्थिक प्रभावों का अध्ययन

DOI: https://doi.org/10.63345/ijrhs.net.v14.i7.4

डॉ. ओम प्रकाश

सहायक प्रोफेसर, अर्थशास्त्र विभाग

राजकीय महाविद्यालय, देवप्रयाग

जनपद टिहरी गढ़वाल, उत्तराखंड – 249301

ORCID iD: https://orcid.org/0009-0006-9922-8209

सारांश— उत्तराखंड एक प्रमुख पर्वतीय राज्य है, जिसकी ग्रामीण अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि, पशुपालन, वानिकी तथा प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित रही है। पिछले कुछ दशकों में रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अन्य आधारभूत सुविधाओं की सीमित उपलब्धता के कारण राज्य के पर्वतीय ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन की प्रवृत्ति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इस अध्ययन का उद्देश्य उत्तराखंड की ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पलायन के सामाजिक एवं आर्थिक प्रभावों का विश्लेषण करना है। अध्ययन में वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक शोध पद्धति का उपयोग करते हुए द्वितीयक स्रोतों, जैसे उत्तराखंड ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग की रिपोर्टों, सरकारी दस्तावेजों, शोध-पत्रों तथा प्रामाणिक हिंदी साहित्य का विश्लेषण किया गया है। अध्ययन से स्पष्ट हुआ कि पलायन के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उत्पादन, स्थानीय रोजगार, कुटीर उद्योग एवं पारंपरिक आर्थिक गतिविधियाँ प्रभावित हुई हैं। इसके साथ ही अनेक गाँवों में जनसंख्या में कमी, कृषि भूमि का अनुपयोगी होना तथा सामाजिक-सांस्कृतिक संरचना में परिवर्तन जैसी समस्याएँ भी सामने आई हैं। दूसरी ओर, प्रवासी परिवारों द्वारा भेजी जाने वाली धनराशि से कुछ परिवारों की आय एवं जीवन स्तर में आंशिक सुधार देखा गया है, किन्तु यह स्थानीय आर्थिक विकास का स्थायी विकल्प सिद्ध नहीं हुआ। अध्ययन के निष्कर्ष बताते हैं कि कृषि विविधीकरण, ग्रामीण पर्यटन, स्वरोजगार, कौशल विकास, कुटीर उद्योगों के संवर्धन तथा आधारभूत सुविधाओं के विस्तार के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाया जा सकता है। समन्वित एवं क्षेत्रविशेष आधारित विकास नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन से पलायन की प्रवृत्ति को नियंत्रित करते हुए उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में सतत एवं समावेशी विकास सुनिश्चित किया जा सकता है।

मुख्य शब्द— उत्तराखंड, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, पलायन, सामाजिक प्रभाव, आर्थिक प्रभाव, ग्रामीण विकास, सतत आजीविका

I. परिचय

उत्तराखंड भारत का एक प्रमुख हिमालयी राज्य है, जिसकी भौगोलिक, सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक विशेषताएँ इसे अन्य राज्यों से अलग पहचान प्रदान करती हैं। राज्य का अधिकांश भाग पर्वतीय होने के कारण यहाँ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था परंपरागत रूप से कृषि, बागवानी, पशुपालन, वानिकी तथा प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित रही है। सीमित कृषि योग्य भूमि, कठिन भौगोलिक परिस्थितियाँ तथा प्राकृतिक संसाधनों पर अत्यधिक निर्भरता के बावजूद ग्रामीण समाज ने लंबे समय तक स्थानीय संसाधनों के माध्यम से अपनी आजीविका को बनाए रखा। किन्तु पिछले कुछ दशकों में बदलती आर्थिक परिस्थितियों, आधुनिक जीवनशैली तथा रोजगार के अवसरों की असमान उपलब्धता ने ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन की प्रवृत्ति को तीव्र गति प्रदान की है।

उत्तराखंड राज्य के गठन (9 नवम्बर 2000) के पश्चात् यह अपेक्षा की गई थी कि पर्वतीय क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं, रोजगार, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार होगा और क्षेत्रीय असंतुलन कम होगा। यद्यपि राज्य के कुछ मैदानी क्षेत्रों में विकास की गति तेज हुई, परन्तु अधिकांश पर्वतीय ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी रोजगार के सीमित अवसर, कृषि की घटती लाभप्रदता, स्वास्थ्य एवं शिक्षा संस्थानों की कमी तथा परिवहन एवं संचार जैसी आधारभूत सुविधाओं का अभाव बना हुआ है। परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में युवा एवं कार्यशील जनसंख्या रोजगार, उच्च शिक्षा तथा बेहतर जीवन-स्तर की तलाश में देहरादून, हल्द्वानी, ऋषिकेश, दिल्ली, चंडीगढ़ तथा अन्य महानगरों की ओर पलायन कर रही है।

ग्रामीण क्षेत्रों से होने वाला यह पलायन केवल जनसंख्या के स्थानांतरण तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका प्रभाव राज्य की सामाजिक एवं आर्थिक संरचना पर भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। कृषि भूमि का अनुपयोगी होना, श्रमशक्ति की कमी, स्थानीय उत्पादन में गिरावट, कुटीर उद्योगों का कमजोर होना तथा अनेक गाँवों का निर्जन होना इसके प्रमुख आर्थिक परिणाम हैं। वहीं दूसरी ओर संयुक्त परिवार व्यवस्था का विघटन, पारंपरिक सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन, महिलाओं पर कार्यभार में वृद्धि तथा लोक संस्कृति एवं सामुदायिक सहभागिता में कमी जैसे सामाजिक प्रभाव भी व्यापक रूप से देखने को मिलते हैं। यद्यपि प्रवासी परिवारों द्वारा भेजी जाने वाली धनराशि से कुछ परिवारों की आय एवं जीवन स्तर में सुधार हुआ है, फिर भी यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था के समग्र विकास का स्थायी विकल्प सिद्ध नहीं हुआ है।

इसी संदर्भ में प्रस्तुत अध्ययन उत्तराखंड की ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पलायन के सामाजिक एवं आर्थिक प्रभावों का समग्र विश्लेषण करने का प्रयास करता है। अध्ययन में पलायन के प्रमुख कारणों, ग्रामीण

© 2026. This article is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).

Vol. 14, Issue 07, July: 2026
ISSN(P) 2347-5404 ISSN(O)2320 771X

आजीविका, कृषि, रोजगार, सामाजिक संरचना एवं सांस्कृतिक परिवर्तनों का विश्लेषण करते हुए यह समझने का प्रयास किया गया है कि किस प्रकार स्थानीय संसाधनों पर आधारित विकास, रोजगार सृजन, कृषि विविधीकरण, ग्रामीण पर्यटन तथा आधारभूत सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के माध्यम से पलायन की प्रवृत्ति को नियंत्रित किया जा सकता है। यह अध्ययन नीति-निर्माताओं, शोधकर्ताओं तथा ग्रामीण विकास से जुड़े हितधारकों के लिए उपयोगी आधार प्रदान करता है तथा उत्तराखंड के पर्वतीय ग्रामीण क्षेत्रों में संतुलित, समावेशी एवं सतत विकास की दिशा में महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रस्तुत करता है।

चित्र 1: उत्तराखंड का मानचित्र एवं प्रमुख पलायन प्रभावित जिले

II. साहित्य समीक्षा

उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन राज्य निर्माण के पश्चात् एक गंभीर सामाजिक-आर्थिक चुनौती के रूप में उभरा है। इस विषय पर उपलब्ध हिंदी साहित्य से स्पष्ट होता है कि पलायन केवल जनसंख्या का स्थानांतरण नहीं है, बल्कि इसका सीधा प्रभाव ग्रामीण अर्थव्यवस्था, कृषि व्यवस्था, सामाजिक संरचना, सांस्कृतिक विरासत तथा स्थानीय विकास पर पड़ता है। विभिन्न शोधों एवं सरकारी अध्ययनों ने इस समस्या के कारणों, प्रभावों तथा संभावित समाधानों का बहुआयामी विश्लेषण प्रस्तुत किया है।

राजेन्द्र पी. ममगैन एवं डी. नरसिंहा रेड्डी के उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में पलायन संबंधी अध्ययन में पाया गया कि राज्य के अधिकांश ग्रामीण परिवारों में दीर्घकालिक एवं स्थायी पलायन की प्रवृत्ति बढ़ी है। अध्ययन के अनुसार रोजगार, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं की अनुपलब्धता पलायन के प्रमुख कारण हैं, जबकि कृषि योग्य भूमि का परित्याग और ग्रामीण उत्पादकता में गिरावट इसके प्रमुख आर्थिक परिणाम हैं।

उत्तराखंड ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग की विभिन्न रिपोर्टों के तुलनात्मक विश्लेषण पर आधारित पूजा एवं अंकित उछोली के अध्ययन में यह निष्कर्ष निकाला गया कि कोविड-19 के बाद राज्य में आंशिक रिवर्स पलायन अवश्य हुआ, किंतु स्थायी समाधान के लिए स्थानीय रोजगार, स्वरोजगार, पर्यटन तथा लघु उद्योगों का विकास आवश्यक है। अध्ययन यह भी दर्शाता है कि सीमावर्ती पर्वतीय क्षेत्रों से निरंतर पलायन राष्ट्रीय सुरक्षा तथा क्षेत्रीय असंतुलन दोनों के लिए चुनौती बन रहा है।

इन्द्र मोहन पन्त एवं प्रो. कैलाश चन्द्र ने अपने शोध में स्पष्ट किया कि उत्तराखंड की लगभग समस्त पर्वतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था कृषि, बागवानी एवं पशुपालन पर आधारित रही है। कृषि की घटती लाभप्रदता, सिंचाई सुविधाओं की कमी तथा विपणन तंत्र के अभाव ने ग्रामीण युवाओं को रोजगार की खोज में पलायन के लिए प्रेरित किया है। उन्होंने स्थानीय संसाधनों पर आधारित आजीविका विकास को पलायन नियंत्रण का प्रभावी उपाय माना है।

हाल के हिंदी शोध में दीपक नाथ एवं डॉ. हेमा ने उत्तराखंड में बढ़ते "भूतिया गाँवों" की समस्या का विश्लेषण करते हुए बताया कि पलायन के कारण कृषि भूमि बंजर होती जा रही है तथा महिलाओं पर कृषि एवं पारिवारिक उत्तरदायित्वों का भार बढ़ रहा है। अध्ययन में सामाजिक संरचना के विघटन, पारंपरिक संस्कृति के क्षरण तथा स्थानीय अर्थव्यवस्था के कमजोर होने को प्रमुख परिणामों के रूप में रेखांकित किया गया है।

उत्तराखंड पलायन आयोग की जिला-आधारित रिपोर्टों का विश्लेषण करते हुए प्रकाशित अध्ययनों में यह पाया गया कि जिन ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा बाजार जैसी आधारभूत सुविधाएँ अपेक्षाकृत विकसित हैं, वहाँ पलायन की दर कम है। आयोग ने कृषि के साथ बागवानी, डेयरी, खाद्य प्रसंस्करण, होम-स्टे, ग्रामीण पर्यटन तथा स्वयं सहायता समूहों को ग्रामीण आय के प्रमुख स्रोतों के रूप में विकसित करने की अनुशंसा की है।

उत्तराखंड के सामाजिक-सांस्कृतिक पक्ष पर उपलब्ध हिंदी साहित्य यह भी इंगित करता है कि पलायन के कारण पारंपरिक लोक संस्कृति, सामुदायिक सहयोग, स्थानीय त्योहारों तथा पारिवारिक संरचना में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। ग्रामीण क्षेत्रों में वृद्धजन एवं महिलाएँ अधिक संख्या में रह जाने से सामाजिक निर्भरता तथा श्रम असंतुलन की समस्या बढ़ी है, जिससे ग्रामीण विकास की गति प्रभावित हुई है।

उपलब्ध साहित्य के समग्र अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि अधिकांश शोध पलायन के कारणों अथवा उसके व्यापक प्रभावों पर केंद्रित हैं, जबकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर सामाजिक एवं आर्थिक प्रभावों के समेकित विश्लेषण वाले अध्ययन अपेक्षाकृत सीमित हैं। विशेष रूप से स्थानीय आय, कृषि उत्पादकता, सामाजिक पूंजी, जनसांख्यिकीय परिवर्तन तथा ग्रामीण जीवन की गुणवत्ता पर संयुक्त प्रभावों का समग्र मूल्यांकन अभी भी शोध का महत्वपूर्ण क्षेत्र बना हुआ है। प्रस्तुत अध्ययन इसी शोध-अंतराल को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड की ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पलायन के सामाजिक एवं आर्थिक प्रभावों का समन्वित विश्लेषण करने का प्रयास करता है।

© 2026. This article is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).

चित्र 2: उत्तराखंड में ग्रामीण पलायन के प्रमुख कारण

III. अध्ययन के उद्देश्य

इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड की ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पलायन के सामाजिक एवं आर्थिक प्रभावों का समग्र विश्लेषण करना है। इसके अंतर्गत पलायन के प्रमुख कारणों की पहचान करना, ग्रामीण कृषि, रोजगार, आय एवं स्थानीय आजीविका पर इसके आर्थिक प्रभावों का अध्ययन करना तथा पारिवारिक संरचना, सामाजिक संबंधों, सांस्कृतिक परंपराओं एवं जनसांख्यिकीय परिवर्तन पर पड़ने वाले सामाजिक प्रभावों का मूल्यांकन करना प्रमुख उद्देश्य हैं। साथ ही, अध्ययन का उद्देश्य ग्रामीण विकास, स्थानीय रोजगार सृजन एवं सतत आजीविका को प्रोत्साहित करने हेतु ऐसे व्यावहारिक सुझाव प्रस्तुत करना भी है, जो पलायन की प्रवृत्ति को कम करने तथा उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों के संतुलित एवं समावेशी विकास में सहायक सिद्ध हों।

IV. शोध पद्धति

प्रस्तुत अध्ययन उत्तराखंड की ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पलायन के सामाजिक एवं आर्थिक प्रभावों का विश्लेषण करने हेतु **वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक** शोध पद्धति पर आधारित है। अध्ययन में गुणात्मक तथा द्वितीयक आँकड़ों के विश्लेषण का उपयोग किया गया है, जिससे विषय के विभिन्न आयामों का समग्र एवं वस्तुनिष्ठ अध्ययन किया जा सके।

अध्ययन के लिए आवश्यक तथ्यों एवं सूचनाओं का संकलन मुख्यतः द्वितीयक स्रोतों से किया गया है। इनमें उत्तराखंड ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग द्वारा प्रकाशित जिला-स्तरीय प्रतिवेदन, भारत सरकार एवं उत्तराखंड शासन के विभिन्न विभागों की रिपोर्टें, जनगणना संबंधी प्रकाशित आँकड़े, नीति आयोग तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय के दस्तावेज, विश्वविद्यालयों में प्रकाशित शोध-प्रबंध, हिंदी एवं शोध-पत्रिकाओं में प्रकाशित शोध-लेख, संदर्भ पुस्तकें तथा अन्य प्रामाणिक अकादमिक स्रोत सम्मिलित हैं। इन स्रोतों से प्राप्त सूचनाओं का विषयानुसार वर्गीकरण एवं तुलनात्मक विश्लेषण किया गया है।

अध्ययन में उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में पलायन के प्रमुख कारणों, कृषि एवं स्थानीय रोजगार पर इसके प्रभाव, ग्रामीण आय, प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग, पारिवारिक संरचना, महिलाओं की भूमिका, सामाजिक-सांस्कृतिक परिवर्तन तथा ग्रामीण विकास की स्थिति का विश्लेषण किया गया है। इसके अतिरिक्त, उपलब्ध साहित्य एवं सरकारी आँकड़ों के आधार पर पलायन के सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों पक्षों का समग्र मूल्यांकन प्रस्तुत किया गया है।

संकलित तथ्यों का विश्लेषण **वर्णनात्मक विश्लेषण पद्धति** के माध्यम से किया गया है, जिसमें विभिन्न अध्ययनों, सरकारी प्रतिवेदनों एवं प्रकाशित आँकड़ों की तुलनात्मक व्याख्या कर निष्कर्ष निकाले गए हैं। अध्ययन के दौरान तथ्यों की विश्वसनीयता एवं प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए केवल प्रमाणित सरकारी दस्तावेजों, मान्यता प्राप्त शोध-पत्रों तथा सत्यापित अकादमिक स्रोतों का ही उपयोग किया गया है।

यह शोध पद्धति उत्तराखंड की ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पलायन के सामाजिक एवं आर्थिक प्रभावों को व्यापक, तथ्यपरक एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने में सहायक सिद्ध होती है तथा भविष्य में ग्रामीण विकास, स्थानीय रोजगार सृजन और पलायन नियंत्रण से संबंधित नीतियों के निर्माण के लिए उपयोगी आधार प्रदान करती है।

V. उत्तराखंड की ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पलायन के सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव

उत्तराखंड एक पर्वतीय राज्य है, जहाँ अधिकांश ग्रामीण आबादी परंपरागत रूप से कृषि, पशुपालन, वानिकी तथा स्थानीय प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित आजीविका पर निर्भर रही है। राज्य गठन (2000) के बाद शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार तथा आधारभूत सुविधाओं की असमान उपलब्धता के कारण पर्वतीय क्षेत्रों से मैदानी नगरों एवं अन्य राज्यों की ओर पलायन में निरंतर वृद्धि हुई। उत्तराखंड ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग के अनुसार वर्ष 2008–2018 के दौरान राज्य की 6,338 ग्राम पंचायतों से **3,83,726 व्यक्तियों ने अस्थायी पलायन** तथा 3,946 ग्राम पंचायतों से **1,18,981 व्यक्तियों ने स्थायी पलायन** किया। इसी अवधि में **734 गाँव पूर्णतः निर्जन** हो गए तथा 565 गाँवों की जनसंख्या 50 प्रतिशत से अधिक घट गई।

पलायन का प्रभाव केवल जनसंख्या में कमी तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा प्रभाव ग्रामीण उत्पादन, कृषि, श्रम शक्ति, स्थानीय बाजार, सामाजिक संरचना तथा सांस्कृतिक जीवन पर भी दिखाई देता है। उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों—पौड़ी गढ़वाल, अल्मोड़ा, टिहरी गढ़वाल, पिथौरागढ़, चंपावत एवं बागेश्वर—में इसका प्रभाव अपेक्षाकृत अधिक देखने को मिलता है।

तालिका 1 : उत्तराखंड में पलायन की प्रमुख स्थिति

संकेतक	आँकड़े
अध्ययन अवधि	2008–2018
अस्थायी पलायन	3,83,726 व्यक्ति
स्थायी पलायन	1,18,981 व्यक्ति

© 2026. This article is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).

प्रभावित ग्राम पंचायतें (अस्थायी)	6,338
प्रभावित ग्राम पंचायतें (स्थायी)	3,946
पूर्णतः निर्जन गाँव	734
50% से अधिक जनसंख्या घटने वाले गाँव	565

स्रोत: उत्तराखंड ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग।

चित्र 3: पलायन को कम करने हेतु समेकित ग्रामीण विकास एवं आजीविका संवर्धन मॉडल

1. आर्थिक प्रभाव

ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण आधार कृषि है, किंतु कार्यशील आयु वर्ग के पलायन से कृषि उत्पादन निरंतर प्रभावित हुआ है। खेती योग्य भूमि का एक बड़ा भाग अनुपयोगी या परती रह गया है क्योंकि कृषि कार्य के लिए आवश्यक श्रमबल उपलब्ध नहीं है। इसके परिणामस्वरूप खाद्यान्न उत्पादन में कमी, कृषि लागत में वृद्धि तथा पारंपरिक फसलों का क्षेत्रफल घटा है। अनेक गाँवों में केवल वृद्धजन एवं महिलाएँ कृषि कार्य संभाल रही हैं, जिससे कृषि का व्यावसायिक विकास बाधित हुआ है।

स्थानीय बाजारों पर भी पलायन का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या कम होने से उपभोग घटा है, जिससे छोटी दुकानों, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यापार तथा पारंपरिक कुटीर उद्योगों की आय प्रभावित हुई है। कई क्षेत्रों में विद्यालय, स्वास्थ्य केंद्र तथा सार्वजनिक सेवाएँ भी सीमित उपयोगकर्ताओं के कारण कमजोर पड़ गई हैं।

दूसरी ओर, कुछ परिवारों को प्रवासी सदस्यों द्वारा भेजी जाने वाली धनराशि (Remittances) से आर्थिक सहायता प्राप्त होती है। इससे परिवारों की आय, बच्चों की शिक्षा तथा आवासीय सुविधाओं में सुधार हुआ है। फिर भी यह आय स्थानीय उत्पादन आधारित अर्थव्यवस्था का विकल्प नहीं बन सकी है क्योंकि इससे स्थानीय रोजगार के अवसरों में वृद्धि नहीं होती।

तालिका 2 : ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर प्रमुख आर्थिक प्रभाव

क्षेत्र	प्रमुख प्रभाव
कृषि	खेती योग्य भूमि परती, उत्पादन में कमी
श्रम शक्ति	युवा श्रमिकों की कमी
पशुपालन	पशुधन एवं डेयरी गतिविधियों में गिरावट
स्थानीय बाजार	व्यापार एवं उपभोग में कमी
ग्रामीण आय	स्थानीय आय में कमी, प्रेषण आय में आंशिक वृद्धि
कुटीर उद्योग	उत्पादन एवं विपणन में गिरावट

2. सामाजिक प्रभाव

पलायन का सामाजिक प्रभाव आर्थिक प्रभावों जितना ही व्यापक है। अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में युवा एवं शिक्षित वर्ग के बाहर जाने से जनसंख्या का आयु-संतुलन प्रभावित हुआ है। परिणामस्वरूप गाँवों में वृद्धजन, महिलाएँ एवं बच्चे अधिक संख्या में रह गए हैं। इससे सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल तथा पारिवारिक सहयोग की पारंपरिक व्यवस्था कमजोर हुई है।

महिलाओं की भूमिका में उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ है। पुरुषों के पलायन के कारण महिलाओं पर कृषि, पशुपालन, घरेलू कार्य तथा पारिवारिक उत्तरदायित्वों का अतिरिक्त भार बढ़ा है। अनेक अध्ययनों में इसे "महिला-प्रधान कृषि" की स्थिति के रूप में वर्णित किया गया है।

पलायन का प्रभाव स्थानीय संस्कृति पर भी स्पष्ट दिखाई देता है। लोक पर्व, पारंपरिक मेले, सामूहिक श्रम (श्रमदान), लोकगीत तथा सामुदायिक सहभागिता में कमी आई है। कई गाँवों में विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या घटने के कारण विद्यालयों का एकीकरण या बंद होना भी देखा गया है। सामाजिक पूंजी (Social Capital) तथा सामुदायिक सहयोग की परंपरा कमजोर होने से ग्रामीण जीवन की गुणवत्ता प्रभावित हुई है।

तालिका 3 : पलायन के प्रमुख सामाजिक प्रभाव

सामाजिक पक्ष	प्रभाव
पारिवारिक संरचना	संयुक्त परिवारों का विघटन
जनसंख्या संरचना	वृद्ध एवं महिला आबादी का अनुपात बढ़ा
शिक्षा	विद्यालयों में छात्र संख्या में कमी
संस्कृति	लोक परंपराओं एवं सामुदायिक गतिविधियों में गिरावट

© 2026. This article is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).

सामाजिक सहयोग	सामुदायिक सहभागिता में कमी
महिलाओं की भूमिका	कार्यभार एवं उत्तरदायित्व में वृद्धि

3. सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभाव

यद्यपि पलायन को सामान्यतः नकारात्मक दृष्टि से देखा जाता है, फिर भी इसके कुछ सकारात्मक परिणाम भी सामने आए हैं। प्रवासी परिवारों की आय में वृद्धि हुई है, आधुनिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच बेहतर हुई है तथा कुछ परिवारों ने ग्रामीण क्षेत्रों में नए मकानों एवं लघु व्यवसायों में निवेश किया है। कोविड-19 के बाद सीमित स्तर पर रिवर्स पलायन ने कृषि, डेयरी, मधुमक्खी पालन, ग्रामीण पर्यटन तथा स्वरोजगार को नया प्रोत्साहन भी दिया।

इसके विपरीत नकारात्मक प्रभाव अधिक व्यापक हैं। निर्जन होते गाँव, कृषि भूमि का परित्याग, प्राकृतिक संसाधनों का अपर्याप्त उपयोग, सीमावर्ती क्षेत्रों का जनशून्य होना तथा ग्रामीण आर्थिक गतिविधियों का कमजोर पड़ना राज्य के संतुलित विकास के लिए गंभीर चुनौती है। वर्ष 2018 तक निर्जन गाँवों की संख्या बढ़कर **1,734** तक पहुँचने तथा 400 से अधिक गाँवों में 10 से कम लोगों के निवास जैसी स्थिति इस समस्या की गंभीरता को दर्शाती है।

तालिका 4 : सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभावों की तुलना

सकारात्मक प्रभाव	नकारात्मक प्रभाव
परिवारों की आय में वृद्धि	कृषि उत्पादन में कमी
शिक्षा एवं स्वास्थ्य तक बेहतर पहुँच	ग्रामीण श्रम शक्ति का अभाव
प्रेषण आय (Remittance)	गाँवों का निर्जन होना
नए कौशल एवं अनुभव	सामाजिक एवं सांस्कृतिक विघटन
सीमित रिवर्स पलायन से स्वरोजगार	स्थानीय अर्थव्यवस्था का कमजोर होना

समग्र रूप से स्पष्ट है कि उत्तराखंड में पलायन ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता, कृषि प्रणाली, स्थानीय रोजगार, सामाजिक संरचना तथा सांस्कृतिक जीवन को गहराई से प्रभावित किया है। यद्यपि प्रेषण आय एवं सीमित रिवर्स पलायन जैसे कुछ सकारात्मक पहलू सामने आए हैं, फिर भी इनके लाभ व्यापक ग्रामीण आर्थिक क्षति की भरपाई नहीं कर पाए हैं। इसलिए स्थानीय संसाधनों पर आधारित रोजगार, कृषि का आधुनिकीकरण, ग्रामीण पर्यटन, कुटीर उद्योग, डिजिटल अवसंरचना तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार ही इस समस्या के दीर्घकालिक समाधान का आधार बन सकता है।

VI. प्रमुख निष्कर्ष एवं चर्चा

प्रस्तुत अध्ययन से स्पष्ट होता है कि उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में पलायन केवल जनसंख्या के स्थानांतरण की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह राज्य की सामाजिक एवं आर्थिक संरचना को व्यापक रूप से प्रभावित करने वाली बहुआयामी समस्या है। उपलब्ध सरकारी प्रतिवेदनों एवं प्रकाशित अध्ययनों के विश्लेषण से यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि रोजगार के सीमित अवसर, कृषि की घटती लाभप्रदता, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव तथा आधारभूत अवसंरचना की कमी पलायन के प्रमुख प्रेरक कारक हैं। विशेष रूप से युवा एवं शिक्षित वर्ग के निरंतर पलायन ने ग्रामीण क्षेत्रों की उत्पादक श्रमशक्ति को कमजोर किया है, जिसके परिणामस्वरूप कृषि उत्पादन, पशुपालन, कुटीर उद्योग तथा स्थानीय व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

अध्ययन से यह भी ज्ञात हुआ कि पलायन के कारण अनेक गाँवों में कृषि योग्य भूमि अनुपयोगी होती जा रही है तथा पारंपरिक कृषि व्यवस्था धीरे-धीरे कमजोर हो रही है। दूसरी ओर, प्रवासी परिवारों द्वारा भेजी जाने वाली धनराशि से कुछ परिवारों की आय एवं जीवन स्तर में सुधार अवश्य हुआ है, किन्तु यह स्थानीय आर्थिक विकास का स्थायी विकल्प सिद्ध नहीं हुआ है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादन आधारित अर्थव्यवस्था के स्थान पर उपभोग आधारित आर्थिक प्रवृत्ति विकसित होती दिखाई देती है।

सामाजिक दृष्टि से पलायन ने संयुक्त परिवार व्यवस्था, सामुदायिक सहयोग, लोक संस्कृति तथा पारंपरिक सामाजिक मूल्यों को प्रभावित किया है। पुरुषों के पलायन के कारण महिलाओं की आर्थिक एवं सामाजिक जिम्मेदारियाँ बढ़ी हैं, जबकि वृद्धजन एवं बच्चों की देखभाल संबंधी चुनौतियाँ भी बढ़ी हैं। अनेक गाँवों में जनसंख्या में कमी के कारण विद्यालयों, स्वास्थ्य सेवाओं एवं अन्य सार्वजनिक सुविधाओं का प्रभावी संचालन भी प्रभावित हुआ है।

चर्चा से यह स्पष्ट होता है कि यदि स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन, कृषि का आधुनिकीकरण, फलोत्पादन, औषधीय पौधों की खेती, ग्रामीण पर्यटन, हस्तशिल्प एवं सूक्ष्म उद्यमों को प्रोत्साहन दिया जाए तथा सड़क, डिजिटल संपर्क, स्वास्थ्य एवं शिक्षा जैसी आधारभूत सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण किया जाए, तो पलायन की गति को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। अतः उत्तराखंड के संतुलित एवं सतत ग्रामीण विकास के लिए ऐसी समेकित विकास नीतियों की आवश्यकता है, जो स्थानीय संसाधनों के वैज्ञानिक उपयोग, रोजगार सृजन तथा जीवन-स्तर में सुधार को प्राथमिकता दें। इससे न केवल पलायन की प्रवृत्ति में कमी आएगी, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को दीर्घकालिक स्थिरता एवं आत्मनिर्भरता भी प्राप्त होगी।

VII. सुझाव

उत्तराखंड की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने तथा पलायन की समस्या को नियंत्रित करने के लिए स्थानीय संसाधनों पर आधारित समेकित विकास रणनीति अपनाना आवश्यक है। सर्वप्रथम पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि का आधुनिकीकरण, जैविक खेती, बागवानी, औषधीय एवं सुगंधित पौधों की खेती तथा पशुपालन को प्रोत्साहन देकर स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ाए जाने चाहिए। ग्रामीण युवाओं के लिए कौशल विकास,

© 2026. This article is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).

स्वरोजगार प्रशिक्षण, स्टार्टअप सहायता तथा सूक्ष्म, लघु एवं कुटीर उद्योगों को वित्तीय एवं तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

ग्रामीण पर्यटन, होम-स्टे, हस्तशिल्प, स्थानीय खाद्य उत्पादों तथा पारंपरिक कला एवं संस्कृति को आर्थिक गतिविधियों से जोड़कर आय के नए स्रोत विकसित किए जा सकते हैं। साथ ही, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएँ, सड़क संपर्क, इंटरनेट एवं डिजिटल अवसंरचना जैसी आधारभूत सुविधाओं का विस्तार पर्वतीय क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए।

इसके अतिरिक्त, ग्राम स्तर पर स्वयं सहायता समूहों, सहकारी समितियों तथा किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) को सशक्त बनाकर सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। सरकार द्वारा पलायन प्रभावित गाँवों के लिए विशेष विकास योजनाएँ, कर प्रोत्साहन तथा निवेश अनुदान लागू किए जाने चाहिए, जिससे स्थानीय स्तर पर आर्थिक गतिविधियों का विस्तार हो सके। इन उपायों के प्रभावी क्रियान्वयन से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सकेगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे तथा उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों से होने वाले अनावश्यक पलायन में उल्लेखनीय कमी लाई जा सकेगी।

VIII. निष्कर्ष

उत्तराखंड की ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पलायन का प्रभाव सामाजिक एवं आर्थिक दोनों दृष्टियों से अत्यंत व्यापक एवं गहन है। प्रस्तुत अध्ययन से स्पष्ट होता है कि रोजगार के सीमित अवसर, कृषि की घटती लाभप्रदता, आधारभूत सुविधाओं का अभाव तथा शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं की असमान उपलब्धता पलायन के प्रमुख कारण हैं। इन कारणों से विशेष रूप से युवा एवं कार्यशील जनसंख्या का निरंतर पलायन हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उत्पादन, पशुपालन, स्थानीय व्यापार तथा कुटीर उद्योगों की गतिविधियाँ प्रभावित हुई हैं। अनेक गाँवों में जनसंख्या में कमी, कृषि भूमि का अनुपयोगी होना तथा सामाजिक-सांस्कृतिक संरचना का कमजोर पड़ना इस समस्या की गंभीरता को दर्शाता है।

अध्ययन यह भी दर्शाता है कि प्रवासी परिवारों द्वारा भेजी जाने वाली धनराशि से कुछ परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है, किंतु यह स्थानीय उत्पादन एवं रोजगार आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था का स्थायी विकल्प नहीं बन सकी है। दूसरी ओर, महिलाओं पर कार्यभार में वृद्धि, संयुक्त परिवार व्यवस्था का विघटन तथा सामुदायिक सहभागिता में कमी जैसे सामाजिक प्रभाव ग्रामीण विकास के लिए नई चुनौतियाँ प्रस्तुत करते हैं।

अतः उत्तराखंड में पलायन की समस्या का समाधान केवल आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि स्थानीय संसाधनों के सतत उपयोग, कृषि विविधीकरण, ग्रामीण पर्यटन, स्वरोजगार, कौशल विकास तथा गुणवत्तापूर्ण आधारभूत सुविधाओं के समन्वित विकास पर आधारित होना चाहिए। यदि सरकार, स्थानीय समुदाय तथा निजी क्षेत्र के सहयोग से रोजगारोन्मुख एवं क्षेत्रविशेष की आवश्यकताओं के अनुरूप विकास नीतियों का प्रभावी क्रियान्वयन किया जाए, तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाया जा सकता है तथा अनावश्यक पलायन की प्रवृत्ति को प्रभावी रूप से नियंत्रित किया जा सकता है। इससे उत्तराखंड के पर्वतीय ग्रामीण क्षेत्रों में संतुलित, समावेशी एवं सतत विकास का मार्ग प्रशस्त होगा।

संदर्भ

[1] उत्तराखंड ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग. (2018). **जनपद पौड़ी गढ़वाल का सामाजिक-आर्थिक विकास एवं पलायन अध्ययन प्रतिवेदन.** देहरादून: उत्तराखंड शासन. उपलब्ध: उत्तराखंड ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग

[2] उत्तराखंड ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग. (2019). **जनपद अल्मोड़ा का सामाजिक-आर्थिक विकास एवं पलायन अध्ययन प्रतिवेदन.** देहरादून: उत्तराखंड शासन. उपलब्ध: आयोग की आधिकारिक वेबसाइट

[3] उत्तराखंड ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग. (2020). **जनपद टिहरी गढ़वाल का सामाजिक-आर्थिक विकास एवं पलायन अध्ययन प्रतिवेदन.** देहरादून: उत्तराखंड शासन. उपलब्ध: आयोग की आधिकारिक वेबसाइट

[4] पूजा एवं उछोली, अ. (2025). **उत्तराखंड में बदलती पलायन प्रवृत्तियाँ और रोजगार स्वरूपों में परिवर्तन—ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग की रिपोर्टों पर केंद्रित एक समाजशास्त्रीय अध्ययन.** *International Journal of Science and Consciousness*, 11(3), 12–19. DOI: 10.5281/zenodo.19434911.

[5] नाथ, दीपक, एवं हेमा. (2026). **भारत के प्रवासी उत्तराखण्ड के परिप्रेक्ष्य में एक अध्ययन.** *International Journal of Advanced Humanities Research.*

[6] सिंह, वर्षा. (2019, 17 जून). **ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने से थमेगा उत्तराखंड का पलायन.** *डाउन टू अर्थ* (हिंदी). लेख

[7] सिंह, वर्षा. (2020). **उत्तराखंड: पलायन आयोग की रिपोर्टों से हासिल क्या होगा?** *डाउन टू अर्थ* (हिंदी). लेख

[8] उत्तराखंड ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग. (2023). **रिवर्स पलायन सर्वेक्षण (अंतरिम प्रतिवेदन).** देहरादून: उत्तराखंड शासन. उपलब्ध: आयोग की आधिकारिक वेबसाइट

[9] उत्तराखंड ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग. (विभिन्न वर्ष). **पलायन एवं सामाजिक-आर्थिक विकास संबंधी जिला प्रतिवेदन.** देहरादून: उत्तराखंड शासन. उपलब्ध: आयोग की आधिकारिक वेबसाइट

[10] उत्तराखंड शासन. **उत्तराखंड ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग: आधिकारिक पोर्टल.** उपलब्ध: आधिकारिक वेबसाइट

© 2026. This article is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).